

एसबीआई का मुनाफा 21,000 करोड़ पार

बैंक के इस दमदार प्रदर्शन का असर शेयर बाजार में भी दिखा

नई दिल्ली, 09 फरवरी. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर तिमाही में 21,028 करोड़ का अब तक का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया, जिसके बाद सोमवार को बैंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में एसबीआई का शेयर 6.6 प्रतिशत उछलकर 1,137 के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया, जो पिछले पांच साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 को तीसरी तिमाही में इतिहास रचते हुए पहली बार 21,000 करोड़ के पार शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है. बैंक के इस दमदार प्रदर्शन का असर शेयर बाजार में



भी साफ दिखाई दिया, जहां सोमवार को एसबीआई का शेयर शुरुआती कारोबार में 6.62 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,137 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. यह पिछले पांच वर्षों में बैंक का सबसे मजबूत एकदिनी प्रदर्शन

माना जा रहा है. बैंक ने स्टैंडअलोन आधार पर 21,028 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है, जो साल-दर-साल आधार पर 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है. इस रिकॉर्ड मुनाफे में एसबीआई न्यूयुअल फंड की अहम भूमिका रही.

इस दौरान बैंक की शुद्ध ब्याज आय भी 9.04 प्रतिशत बढ़कर रु . 45,190 करोड़ पर पहुंच गई. आगे के आउटलुक को लेकर बैंक प्रबंधन ने सकारात्मक रुख अपनाया है. एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए लोन ग्रोथ का लक्ष्य बढ़ाकर 13-15 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 12-14 प्रतिशत था. बैंक को कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों सेगमेंट में मजबूत क्रेडिट डिमांड की उम्मीद है. वर्तमान में एसबीआई के पास करीब 8 लाख करोड़ की लोन पाइपलाइन है, जिसमें से 74.41 लाख करोड़ के लोन पहले ही मंजूर हो चुके हैं. एसेट कालिटी के मोर्चे पर भी बैंक की स्थिति मजबूत बनी हुई है.

आइटेल ने पेश किया ए100 स्मार्टफोन

नई दिल्ली, 09 फरवरी. देश की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी आईटेल ने सोमवार को नया स्मार्टफोन ए100 लॉन्च किया है जिसकी कीमत 6,799 रुपये से शुरू है. कंपनी ने बताया कि इसमें अल्ट्रालिक फीचर दिया गया है, जो नेटवर्क न होने की स्थिति में भी कॉल करने का विकल्प देता है. यह फीचर खास तौर पर उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है, जो कम या कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में रहते हैं. ए100 को मिलिट्री ग्रेड प्रमाणन (एमआईएल-एसटीडी-810 एच) के साथ बाजार में उतारा गया है जिससे यह रफ इस्तेमाल को भी झेलने में सक्षम है. आईटेल ने ए100 स्मार्टफोन को 64जीबी स्टोरेज के साथ दो रैम संस्करणों में पेश किया है. पहले संस्करण में तीन जीबी रैम है जिसे आठ जीबी तक बढ़ाया जा सकता है.

कमजोर डॉलर से गोल्ड-सिल्वर में उछाल



अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 4 फरवरी के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया, जिससे डॉलर में कीमत तय होने वाली कीमती धातुएं विदेशी निवेशकों के लिए सस्ती हो गईं और मांग को समर्थन मिला. भले ही ईरान के शीर्ष राजनयिक ने अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता को अच्छी शुरुआत बताया हो, लेकिन यूरैनियम संवर्धन को लेकर तेहरान के रुख ने बाजार की चिंताओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया है. जानकारों का मानना है कि जियोपॉलिटिकल तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है.

उछाल देखने को मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स सुबह 10.45 बजे 1.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,57,484 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा. वहीं, सिल्वर

मार्च फ्यूचर्स में 4.81 प्रतिशत की मजबूती दर्ज की गई और कीमत रु. 2,61,900 प्रति किग्रा तक पहुंच गई. दिने के कारोबार में इससे पहले चांदी की कीमतों रु. 2,64,885 प्रति किलो तक पहुंच गई थीं.



शेयर बाजारों में तेजी जारी

बीएसई का सेंसेक्स 485 अंक चढ़ा

मुंबई, 09 फरवरी. अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते और विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी रही और बीएसई का 3 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 485.35 अंक (0.58 प्रतिशत) की बढ़त में 84,065.75 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 173.60

अंक यानी 0.68 प्रतिशत ऊपर 25,867.30 अंक पर बंद हुआ. अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर दोनों देशों की ओर से 07 फरवरी को जारी साझा वक्तव्य में इसकी मुख्य बातों का खुलासा किया गया था. इससे आज निवेश धारणा को मजबूती मिली और बाजार में तेजी रही. बाजार में आज चौरफा लिवाली रही.

फिशरीज स्कीम में 4.76 लाख केसीसी जारी

नई दिल्ली, 9 फरवरी. सरकार ने बताया कि फिशरीज लेंडिंग स्कीम के तहत जून 225 तक लगभग 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और 3,214 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है. इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 13, करोड़ से अधिक के ऋण मंजूर किए गए हैं, जिससे सेक्टर में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिला है.

सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े पैमाने पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराते हुए फिशरीज लेंडिंग स्कीम के तहत जून

जून 2025 तक लगभग 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए हैं और 3,214.32 करोड़ की राशि वितरित की है. इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फिशरीज सेक्टर के लिए 13,000 करोड़ से अधिक के ऋण को मंजूरी दी गई है, जिससे जलीय कृषि और अवसंरचना विकास को गति मिली है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत जुलाई 2025 तक 178 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 6,369 करोड़ से अधिक की फाइनंसिंग शामिल है. वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड इस सेक्टर का प्रमुख शॉर्ट-टर्म क्रेडिट साधन बना हुआ है, जिसमें 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जो समय पर भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है. 7,522.48 करोड़ के कॉर्पस वाला मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास फंड की वैधता मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है.

अनुसार, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत जुलाई 2025 तक 178 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 6,369 करोड़ से अधिक की फाइनंसिंग शामिल है. वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड इस सेक्टर का प्रमुख शॉर्ट-टर्म क्रेडिट साधन बना हुआ है, जिसमें 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जो समय पर भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है. 7,522.48 करोड़ के कॉर्पस वाला मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास फंड की वैधता मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है.

अनुसार, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत जुलाई 2025 तक 178 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 6,369 करोड़ से अधिक की फाइनंसिंग शामिल है. वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड इस सेक्टर का प्रमुख शॉर्ट-टर्म क्रेडिट साधन बना हुआ है, जिसमें 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जो समय पर भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है. 7,522.48 करोड़ के कॉर्पस वाला मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास फंड की वैधता मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है.

अनुसार, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत जुलाई 2025 तक 178 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 6,369 करोड़ से अधिक की फाइनंसिंग शामिल है. वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड इस सेक्टर का प्रमुख शॉर्ट-टर्म क्रेडिट साधन बना हुआ है, जिसमें 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जो समय पर भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है. 7,522.48 करोड़ के कॉर्पस वाला मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास फंड की वैधता मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है.

अनुसार, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत जुलाई 2025 तक 178 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 6,369 करोड़ से अधिक की फाइनंसिंग शामिल है. वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड इस सेक्टर का प्रमुख शॉर्ट-टर्म क्रेडिट साधन बना हुआ है, जिसमें 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जो समय पर भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है. 7,522.48 करोड़ के कॉर्पस वाला मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास फंड की वैधता मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है.

अनुसार, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत जुलाई 2025 तक 178 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 6,369 करोड़ से अधिक की फाइनंसिंग शामिल है. वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड इस सेक्टर का प्रमुख शॉर्ट-टर्म क्रेडिट साधन बना हुआ है, जिसमें 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जो समय पर भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है. 7,522.48 करोड़ के कॉर्पस वाला मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास फंड की वैधता मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है.

अनुसार, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत जुलाई 2025 तक 178 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 6,369 करोड़ से अधिक की फाइनंसिंग शामिल है. वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड इस सेक्टर का प्रमुख शॉर्ट-टर्म क्रेडिट साधन बना हुआ है, जिसमें 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जो समय पर भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है. 7,522.48 करोड़ के कॉर्पस वाला मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास फंड की वैधता मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है.

समाचार विशेष

झारखंड नगर निकाय चुनाव में हुए बड़े खेल

भाजपा और संघ में निकले कई बागी, चला दल बदल का सिलसिला

रांची. झारखंड में चल रहे नगर निकाय चुनाव भले ही औपचारिक रूप से दलीय आधार पर नहीं हो रहे हों. लेकिन राजनीति का असर इन चुनावों में साफ नजर आ रहा है. चुनाव चिन्ह भले ही पार्टियां नहीं दे रही हैं, पर प्रत्याशियों को समर्थन देकर वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं.

इसी वजह से इस बार नगर निकाय चुनाव भी दलबदल से अछूता नहीं रहा है. राज्य के अलग-अलग राजनीतिक दलों ने नगर निगमों में महापौर और नगर परिषद व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद को



लेकर खास रणनीति बनाई. कई दलों ने जिलाध्यक्षों से संभावित उम्मीदवारों के नाम मंगवाए और आपसी मंथन के बाद समर्थन देने

का फैसला किया. समर्थन पाने की होड़ में कई नेताओं ने पार्टी बदलने से भी परहेज नहीं किया. धनबाद नगर निगम इसका बड़ा उदाहरण है.

यहां के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता चंद्रशेखर अग्रवाल ने नामांकन के पहले ही दिन पर्चा भर दिया था, जबकि बीजेपी ने उस समय किसी को समर्थन देने का फैसला नहीं किया था. बाद में पार्टी ने संजीव अग्रवाल को समर्थन देने की घोषणा कर दी. इसके बाद चंद्रशेखर अग्रवाल ने तुरंत झामुमो की सदस्यता ले ली.

एक अन्य मामले में बीजेपी ने झामुमो विधायक दशरथ गगरई के भाई विजय गगरई को पार्टी में शामिल किया और बाद में उन्हें समर्थन भी दिया. इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई. रांची नगर निगम में भी स्थिति कुछ ऐसी

देवघर नगर निगम में मिला उलटफेर

देवघर नगर निगम में भी उलटफेर देखने को मिला. बीजेपी ने महापौर पद के लिए रीता चौरसिया को समर्थन देने का फैसला किया, जबकि पार्टी के ही नेता बाबा बलियासे ने भी नामांकन भर दिया. पहले चर्चा थी कि पार्टी बाबा बलियासे को समर्थन दे सकती है. इन सभी घटनाओं से साफ है कि दलीय चुनाव न होने के बावजूद नगर निकाय चुनाव पूरी तरह राजनीति से जुड़े हुए हैं. समर्थन, रणनीति और दलबदल ने इन चुनावों को रोचक बना दिया है.

ही रही. बीजेपी ने महापौर पद के लिए रोशनी खलवो को समर्थन देने का निर्णय लिया. लेकिन इससे पहले ही पार्टी के एसटी मोर्चा के मीडिया प्रभारी और कार्यालय मंत्री राजेंद्र मुंडा अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर चुके थे.

ममता क्या अब भी अकेले चलेंगी?



दूसरी ओर राहुल गांधी ने इस मसले पर चुप्पी साधी है. ध्यान रहे सबसे पहले एसआईआर के खिलाफ राहुल ही सड़क पर उतरे थे, जब उन्होंने बिहार में 15 दिन की यात्रा की थी.

अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों एसआईआर पर चुप हैं. कांग्रेस को पता है कि पश्चिम बंगाल में उसका बहुत कुछ दांव पर नहीं है. इसलिए उसके नेता तुणमूल कांग्रेस के साथ मिल कर एसआईआर का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं. कांग्रेस के एक जानकार नेता कहना है कि ममता बनर्जी जान बूझकर राहुल गांधी की अनेदेखी करती हैं. राहुल जो मुद्दे उठाते हैं उस पर वे चुप रह जाती हैं.

कोलकाता. संसद के बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के बीच कमाल की एकजुटता बनी है. विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं और उनके उठाए एजेंडे का समर्थन कर रही हैं. हालांकि तुणमूल कांग्रेस के सांसद अब भी अलग मुद्दा उठाए हुए हैं. इसका तात्कालिक कारण यह है कि ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गईं.

दो फरवरी को उनको चुनाव आयोग से मिलना था, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को खूब हमला किया. अगले दिन तीन फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार और चुनाव आयोग को

पेज एक का शेष

जवानों का सम्मान

यादव, संदीप शर्मा, लोकपाल धाकड़, कुष्णा श्रेष्ठ, जितेन्द्र सिंह पटेल, वीर सिंह, शकरचंद सरयाम, सुनील परियार, चन्द्रकांत पांडेय, सत्यम द्वेदी, सुनील यादव, देवराज कलमें, सुरेन्द्र सिंह मार्को, सुशील उईके, रामलाल भील, उमेश चन्द्र दुबे, संतोष कुमार मरावी, प्रदीप कुमार परते, राजा मालवीय, विशाल कुमार सिंह, दीपक पवार, कन्हैया मरकाम, सुनील सिंह कुशवाह, मूलायम सिंह, वरूण देव सिंह चाहर, मुनीष कुमार द्विवेदी, नीलेश, महेंद्र, सिंह, रवि कुमार यादव, छठु यादव, सलेश कुमार द्विवेदी, संजु शर्मा एवं जिला पुलिस बल के नरेंद्र सोनवे शामिल हैं.

14 जून 2025 को हुई थी मुठभेड़ : बता दें कि 14 जून 2025 को बालाघाट

जिले के रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवामावादर-कटेश्रिरिया पहाड़ी जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में हॉक फोर्स के जवानों ने अद्वितीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया था. इस मुठभेड़ में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के जीआरवी डिवीजन के मलाजखंड दलम के 04 एरिया कमेटी सदस्यों - रीता उर्फ तुब्बी, श्रीरंगु हिड़ामी उर्फ देवचंद, सुमन, ईमला उर्फ तुलसी एवं रवि मंडावी उर्फ बदर को मार गिराने में हॉक फोर्स के जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

ये रहे मौजूद : कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, सांसद भारती पारधी, विधायक सर्वो राजकुमार करहि, गौरव पारधी, विवेक पटेल, मधु

भगत, पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वय गौरीशंकर बिसेन, प्रदीप जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरसवार, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य मौसम बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व विधायक रमेश भट्टेरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, नक्सल विरोधी अभियान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी व्यांकटेश्वर राव, सीआरपीएफ की आईजी नीतू सिंह भट्टटायारी, बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक ललित शाव्येवार, जबलपुर संभाग के कमिश्नर धनंजय सिंह, बालाघाट जोन के पुलिस उपमहानिरीक्षक विनीत जैन, कलेक्टर मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा सुरक्षा बलों के जवान उपस्थित रहे.

विशेष भाजपा अध्यक्ष को अब अलॉट हुआ शिबू सोरेन वाला बंगला

राहुल गांधी के पड़ोसी नहीं बनेंगे नितिन नवीन

नई दिल्ली. नितिन नवीन की बीजेपी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी के बाद केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, केंद्र की ओर से नितिन नवीन को लुटियंस दिल्ली के प्रतिष्ठित इलाके में स्थित 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला दिया गया है.

सूत्रों के अनुसार, पहले नितिन नवीन को 9 सुनहरी बाग लेन का बंगला दिया जा रहा था, लेकिन वह उन्हें पसंद नहीं आया. इसके बाद उन्होंने वैकल्पिक बंगला के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद उन्हें 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला दिया गया है. बता दें कि यह टाइप-8 श्रेणी का सरकारी बंगला है और इसमें पहले झारखंड के पूर्व



सीएम शिबू सोरेन रहते थे.

टाइप-8 सरकारी बंगला बेहद हाई ग्रेड माना जाता है. जानकारी के मुताबिक, इस बंगले में 8 बड़े कमरे होते हैं. जिनमें 5 से 6

बेडरूम, विशाल ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, मॉडर्न किचन और डाइनिंग एरिया शामिल हैं. इसके अलावा निजी गैराज, स्टर रूम और स्टाफ क्वार्टर की अलग व्यवस्था भी रहती है. टाइप-8 सरकारी बंगले के पूरे परिसर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और 24 घंटे सुरक्षाबलों की तैनाती रहती है.

बंगले से शिबू सोरेन का कनेक्शन- जानकारी के अनुसार, झारखंड के दिवंगत मुख्यमंत्री शिबू सोरेन दशकों तक इस बंगले में रहे थे. बतौर सांसद (लोकसभा और राज्यसभा) उन्हें यह बंगला आवंटित हुआ था. बतौर केंद्रीय मंत्री भी वह इसी बंगले में रहते थे. 4 अगस्त 2025 को उनके निधन तक यह बंगला उनके आधिकारिक निवास के रूप में दर्ज था.

नितिन नवीन के पड़ोसी कौन होंगे?

मोतीलाल नेहरू मार्ग पर कई बड़े राजनेताओं के आवास हैं. इनमें जेपी नड्डा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हैं. पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को इस वक्त 7-बी, मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला आधिकारिक आवास आवंटित हो रहा है. वहीं 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाले बंगले में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह रहते थे. उनसे पहले यहां दिल्ली की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थीं. मोतीलाल नेहरू मार्ग के पास ही 10 जनपथ आवास है, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रहती हैं.